

नर्मदा जल विवाद के बारे में  
प्रधान मंत्री का निर्णय

\*18. श्री फूल चन्द वर्मा :  
श्री पी० जी० भावलंकर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने  
की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद के बारे में  
प्रधान मंत्री 1 जनवरी, 1974 को अपना  
निर्णय घोषित करने वाली थीं; और

(ख) इस निर्णय को घोषित करने में  
दिलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त निर्णय  
कब तक घोषित किये जाने की संभावना  
है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री  
(श्री सिद्धेश्वर प्रताप) : (क) जी,  
नहीं ।

(ख) यह बड़ी जटिल समस्या है तथा  
इसके सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार  
किया जा रहा है । यह ठीक-ठीक बताना  
कठिन है कि पंचाट कब तक घोषित कर  
दिया जाएगा ।

तेल उत्पादक देशों द्वारा लाभ के बारे  
में रखी गई शर्तें

\*19. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या  
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में स्थिरता लाने की  
दृष्टि से कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले  
देशों ने यह शर्त रखी है कि तेल की खपत  
करने वाले देश अपने देश में तेल कम्पनियों-  
क; 100 प्रतिशत से अधिक मुनाफा न लेने  
दें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को  
जानकारी है कि भारत में तेल कम्पनियों कितना  
मुनाफा ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह मुनाफा कितने  
प्रतिशत है और इस बारे में सरकार की क्या  
प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ( श्री  
देवकांत बरुआ ) : (क) से (ग) .  
सरकार को मिली सूचना के अनुसार तेल  
कम्पनियों को तेल उत्पादन करने वाले देशों  
से जिन वाय-बक मूल्यों पर कच्चा तेल  
उपलब्ध होगा, उन पर अभी बातचीत  
जारी है । अतः तेल कम्पनियों को होने वाले  
लाभों की मात्रा का निर्धारण करना सम्भव  
नहीं है ।

रेलवे के अपने बिजलीघर

\*20. ड० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :  
श्री ई० वी० विश्वे पाटिल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे  
कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली के संकट,  
डीजल तेल के अभाव तथा गाड़ियों के विद्युत्  
चालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए  
रेलवे ने अपने बिजलीघर बनाने का निर्णय  
किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना  
का प्रारूप क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री मोहम्मद  
शफी कुरेशी ) : (क) जी हां ।

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों में अपने  
तीन बिजलीघर स्थापित करना शामिल है  
जिनमें से एक एक बिजलीघर पश्चिम  
बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थापित  
किया जायेगा । आर्थिक परिचालन के लिए  
इनका आपसी सम्बन्ध बिजली बोर्ड की